कॉरपोरेट कानून में कॅरिअर

विजय प्रकाश श्रीवास्तव

हाल ही में देश के एक प्रमुख वित्तीय दैनिक में, इस लेख की थीम से संबंधित दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें आई थीं. पहली रिपोर्ट का शीर्षक था ''भारतीय कंपनियां अपनी इन-हाउस कानूनी टीमों का विस्तार कर रही हैं''. अन्य रिपोर्ट में 2018 की पहली छमाही में पेशेवरों को काम पर रखने के मामले में कानूनी और शिक्षा क्षेत्रों में सबसे अधिक गतिशीलता की बात कही गई थी. कानून की डिग्री के साथ कॉरपोरेट जगत में प्रवेश करने के इच्छुक लोगों को इससे खुश होना चाहिए.

कानून का अर्थ है कानूनी रूप से लागू होने वाले नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों की एक प्रणाली. कॉरपोरेट कानून कंपनियों के लिए लागू नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को संदर्भित करता है. शर्तों के अधीन एक कंपनी भी एक कानूनी इकाई है और ऐसी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से कई कानून होते हैं.

अध्ययन के एक विषय के रूप में कानून दशकों से अस्तित्व में है. हालांकि इस क्षेत्र में कॅरिअर के अवसर 20-25 साल पहले नहीं थे. यह अधिकांश छात्रों के लिए अध्ययन का एक प्रिय विषय था. कानून का अध्ययन करने का मतलब बाद में एक वकील बनना और अदालत में, ज्यादातर निचली अदालतों में अभ्यास करना था. कानून के अधिकांश स्नातक जिला और तालुका स्तर की अदालतों में अभ्यास कर सकते थे, जिनमें से कुछ वकील ही वर्षों की लंबी सेवा के बाद उच्च एवं सर्वोच्च न्यायालय में बार में शामिल हो सकते थे. कुछ कानूनी प्रकाशकों ने इस पेशे की प्रतिष्ठा को बढ़ाया. फिर भी विषय को शायद ही कभी इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन जो कॅरिअर की दृष्टि से बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित करते थे, की लीग में रखा जा सकता था.

आज स्थिति पूरी तरह से बदल गई है. वास्तव में कानून उन विषयों की सूची में सबसे ऊपर है जिनके अध्ययन में एक पूर्ण प्रतिमान देखा गया है. आज कई होनहार छात्र कानून का अध्ययन करने और उसमें एक कॉरपोरेट कॅरिअर बनाने के इच्छुक हैं. यह प्रतिमान बदलाव मुख्य रूप से निम्नलिखित स्थितियों या कारणों से हुआ है:

कानूनी शिक्षा का व्यवसायीकरण: कानून पाठ्यक्रम पहले विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में पढ़ाया जाता था. कानूनी शिक्षा के लिए विशेष रूप से संस्थानों की कमी थी. भारत के नेशनल लॉ स्कूल यूनिवर्सिटी जैसे निकायों की स्थापना आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पर हुई और इस विषय के अध्ययन के लिए एक नई पहचान बनाई.

बाजारों और उपभोक्तावाद का विस्तार: भारतीय बाजारों और व्यवसायों का बड़े पैमाने पर विस्तार हो रहा है और उपभोक्तावाद निरंतर आधार पर सुदृढ़ता हासिल कर रहा है. वित्तीय सेवाओं सहित उत्पादों और सेवाओं की मांग बढ़ती जा रही

है. यह जनशक्ति की आवश्यकता को भी प्रभावित करती है. कानून सहित विभिन्न विषयों में पेशेवरों की मांग में वृद्धि, इस बात का प्रमाण है.

विनियमों में वृद्धि : हालांकि यह उदारीकरण का युग है और सरकारें व्यापार में सरलता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं, निष्पक्ष व्यवहार, कॉरपोरेट प्रशासन और कर अनुपालन इत्यादि सुनिश्चित करने के लिए कुछ नियम होने चाहिएं. इनका कानूनी अर्थ है और कई मामलों में कंपनियां चाहती हैं कि आवश्यक विशेषज्ञता धारी कानूनी पेशेवर इन कार्यों का हस्तन करें.

कानूनी नौकरियों का निगमीकरण : देश में व्यावसायिक संस्कृति हाल के वर्षों में अधिक परिष्कृत हुई है. व्यावसायिक रूप से शिक्षित, सक्षम लोग सभी क्षेत्रों में अधिक पसंद हैं. बड़ी कंपनियों ने अपनी कानूनी टीम रखने का निर्णय लिया है और छोटी कंपनियों ने इसका अनुसरण किया है.

भारतीय बाजार में विदेशी संस्थाओं की बढ़ती रुचि : भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और उभरते बाजारों में एक अग्रणी है. चीन के बाद इसकी सबसे बड़ी आबादी है. बाजार का व्यापक आकार वैश्विक संस्थाओं, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है. निवेशक एक नए बाजार में प्रवेश करने के लिए इन विभिन्न कानूनी प्रावधानों को जानना चाहते हैं ताकि यहां उनका प्रवेश बिना किसी कानूनी जटिलताओं के सुचारू रूप से हो सके. कॉरपोरेट वकील उनकी मदद के लिए आते हैं.

कानून का अध्ययन

किसी भी तरह के पेशेवर कॅरिअर के लिए, आपको विषय में कम से कम स्नातक डिग्री की आवश्यकता होती है. शायद यही एकमात्र विषय है जिसे डिग्री हासिल करने के लिए डिग्री की आवश्यकता होती है. बैचलर ऑफ लॉ को आमतौर पर एलएलबी योग्यता के रूप में जाना जाता है, जिसमें तीन वर्ष के अध्ययन की आवश्यकता होती है और 10 + 2 + 3. शिक्षा चक्र पूरा करने के बाद आप इसमें शामिल हो सकते हैं. अब कानून की डिग्री प्रदान करने वाले एकीकृत पाठ्यक्रम बड़े पैमाने पर उपलब्ध हैं जिन्हें 10 + 2 के बाद किया जा सकता है. इस तरह के पाठ्यक्रमों की अवधि पांच वर्ष है. यह आपको स्नातक और एलएलबी दोनों करने के लिए एक वर्ष बचाता है. जबकि एक के बाद दूसरा पाठ्यक्रम करने में छह वर्ष लगते हैं.

यदि आप बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.बी.ए. आदि के बाद 3 वर्ष के कोर्स के लिए जा रहे हैं तो आप इसमें शामिल हो सकते हैं. ऐसे लोग भी हैं जो अपनी स्नातकोत्तर योग्यता के बाद कानून की डिग्री प्राप्त करते हैं. तो आप ऐसे लोगों को पा सकते हैं जिनके पास एम.ए., एल.एल.बी., एम.एस.सी.; एलएलबी आदि जैसी योग्यताएं हैं.

पांच वर्ष के पाठ्यक्रम बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम, बी.बी.ए. इत्यादि के युग्मक में उपलब्ध हैं. उपलब्धता अलग-अलग संस्थान में भिन्न-भिन्न हो सकती हैं अर्थात सभी संस्थानों में सभी युग्मक उपलब्ध नहीं हैं. यद्यपि कानून में एक कॉरपोरेट कॅरिअर के लिए एलएलबी की डिग्री पर्याप्त मानी जाती है, लेकिन कुछ लोग स्नातकोत्तर योग्यता (एलएलएम) भी जोड़ना पसंद करते हैं. कानून पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा

प्रवेश परीक्षा

एलएलबी और एलएलएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कई प्रवेश परीक्षाएं होती हैं. इनमें से सबसे सामान्य है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) जो सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कानून संस्थानों का प्रवेश द्वार है. यह परीक्षा कई केंद्रों पर आयोजित की जाती है और इसमें निम्नलिखित में से बहुविकल्प प्रकार के प्रश्न होते हैं :-

कॉम्प्रिहेंशन सहित अंग्रेजी, लीगल एप्टीट्यूड (संवैधानिक कानून, न्यायशास्त्र, अनुबंध के कानून आदि के बारे में जागरूकता की जांच करने के लिए), तर्क संगतता, सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाएं, एलीमेंट्री मैथमेटिक्स एवं संख्यात्मक अभिरुचि शामिल है.

लगभग 50 अन्य संस्थान अपने एल.एल.बी. प्रोग्राम्स में प्रवेश के लिए क्लैट स्कोर पर विचार करते हैं.

लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट इंडिया एक निजी एजेंसी द्वारा संचालित एक पेपर और पेंसिल टेस्ट है. कई निजी संस्थानों द्वारा अपने स्नातक और स्नातकोत्तर कानून पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए स्कोर स्वीकार किए जाते हैं. प्रश्न विश्लेषणात्मक तर्क, तर्क (दो भागों में) और पठन की समझ से संबंधित होते हैं.

कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्य के विश्वविद्यालयों में कई पाठ्यक्रमों (कानून में पाठ्यक्रम सहित) के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षण निकायों की स्थापना की है. उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में एम.एच. सी.ई.टी. है जबकि केरल में के.ई.ए.एम. है. एक अन्य उदाहरण तेलंगाना स्टेट कॉमन लॉ एंट्रेंस टेस्ट है.

अपनी स्वयं की परीक्षा आयोजित करने वाले कई विश्वविद्यालय हैं. बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कई अन्य विश्वविद्यालय इसमें शामिल किए जा सकते हैं.

आप क्या करेंगे?

कॉरपोरेट वकील के रूप में आपको कॉरपोरेट जगत से संबंधित कानूनी घटनाओं से परिचित होने की आवश्यकता होती है. कार्यों में निम्नलिखित शामिल है

- विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित कानूनों और अध्यादेशों एवं कॉरपोरेट क्षेत्र में सेवारत अर्ध-न्यायिक निकायों के कानून और निर्णयों का अध्ययन और अद्यतन रहना
- कंपनियों और उनके बीच कानूनी विवाद के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और अदालत के पिछले निर्णयों का अध्ययन करना.
- नियमों, कानूनों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करना और निगरानी करना.
- कंपनी के शीर्ष प्रबंधन के लिए अदालत के निर्णयों और उनकी बाधाओं की व्याख्या करना और
- कागजी कार्रवाई जैसे प्लेंट्स तैयार करना, दस्तावेजों की सूची बनाना
- अपनी कंपनी की ओर से कोर्ट केस फाइल करना और कोर्ट केस के दौरान कंपनी का प्रतिनिधित्व करना और कंपनी के खिलाफ दर्ज मामलों में कंपनी का बचाव भी करना.
- कंपनी से संबंधित अदालती मामलों के घटनाक्रम की जानकारी शीर्ष प्रबंधन को देना
- अनुबंधों का मसौदा तैयार करना, जांच एवं सुलह-समझौते
- विशेष मामलों जैसे विलय और अधिप्रापण, अधिग्रहण आदि में कानूनी मुद्दों को संभालना.

अध्ययन कहां से करें:-

लगभग हर विश्वविद्यालय और उनके संबद्ध कॉलेज कानून में पाठ्यक्रम चलाते हैं. देश भर में स्थित 19 राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों की सूची निम्नानुसार है-

नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडी एंड रिसर्च (एन.ए.एल.एस.ए.आर.) यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी एनएलएसआईयू, बेंगलुरु

नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एन.एल.आई.यू.), भोपाल

गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (जी.एन.एल.यू.), गांधीनगर

दामोदराम संजीवय्या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (डी.एस.एन.एल.यू.), विशाखापत्तनम

हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एच.एन.एल.यू.), रायपुर

तमिलनाडु लॉ स्कूल (टी.एन.एन.एल.एस.), तिरुचिरापल्ली

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और न्यायिक अकादमी, असम

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज़ (एन.यू.ए.एल.एस.), कोच्चि

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ (एन.यू.एस.आर.एल.), रांची

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एन.एल.यू.), जोधपुर

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा (एन.एल.यू.ओ.), कटक

महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एम.एन.एल.यू.) मुंबई, नागपुर और औरंगाबाद

राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (आर.जी.एन.यू.एल.), पंजाब

चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (सी.एन.एल.यू.), पटना

राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (आर.एम.एल.एन.एल.यू.), लखनऊ

पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय (डब्ल्यू.बी.एन.यू. जे.एस.), कोलकाता

कैंपस सेलेक्शन

अब अधिक से अधिक कंपनियां प्रतिष्ठित लॉ कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से अपनी कानूनी जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करना पसंद करती हैं. ऐसी कंपनियों में टाटा एआईजी जैसे बीमा सेवा प्रदाता, अन्य कंपनियों में अमर चंद मंगलदास जैसी कानूनी परामर्शदाता कंपनी शामिल हैं. राष्ट्रीय कानून विश्वविद्यालयों से पास होने वाले स्नातक और स्नातकोत्तर की ऐसी प्लेसमेंट प्रक्रियाओं के बाद बहुत मांग की जाती है.

जैसे ही आप अपनी कानून की डिग्री पूरी करते हैं, आपको कानून की अदालत में कानूनी अभ्यास (वकील के रूप में) के लिए योग्य बनाने हेतु बार काउंसिल में खुद को पंजीकृत करवाना चाहिए. कई चयन प्रक्रियाओं में इसे एक आवश्यकता माना जाता है.

पाठ्यक्रम युग्मक

कानून में डिग्री के साथ मानव संसाधन या औद्योगिक संबंधों या कंपनी सेक्रेट्रीशिप में एक योग्यता कॉरपोरेट जगत में बहुत मूल्यवान है. आपको अपने कॅरिअर की प्राथमिकताओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए और अतिरिक्त योग्यता का विकल्प चुनने से पहले समय की आवश्यकता को भी समझें.

कॅरिअर की तलाश कहां करें

कंपनियों को प्रायः अनुपालन, अपने विरुद्ध दायर किए गए मुकदमों या उनसे मांगे गए स्पष्टीकरण जैसे कानूनी मुद्दों का सामना करना पड़ता है. कई मामलों में उन्हें अपने हितों की रक्षा के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ता है. इसके लिए कम्पनियां विभागीय विशेषज्ञ रखना पसंद करती हैं और इस तरह योग्यताप्राप्त कानूनी व्यवसायियों के लिए सृजित होते हैं.

रोज़गार के अवसर निम्नलिखित में उपलब्ध हो सकते हैं:-

बैंक : सभी श्रेणी के बैंक (सार्वजनिक/ निजी क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदेशी बैंक, भुगतान बैंक आदि को कानूनी कर्मियों की आवश्यकता होती है. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कानून स्नातक एक निर्धारित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भर्ती किए जाते हैं.

बीमा कंपनियां : जीवन और सामान्य बीमा से निपटने वाली बीमा कंपनियों के समक्ष कई कानूनी मुद्दे आते हैं. भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंट फायर और जनरल इंश्योरेंस सरकारी कंपनियां हैं. निजी बीमा कंपनियों की एक लंबी सूची है, जिनमें से कई के विदेशी भागीदार हैं.

वित्तीय कंपनियां : इसमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), मर्चेंट और निवेश बैंकर, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अन्यों में ऋण देने वाली कंपनियां शामिल हैं. वित्तीय स्टार्टअप के लिए भी कानूनी विशेषज्ञों की आवश्यकताएं हो सकती हैं.

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.), भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), म्यूचुअल फंड्स एसोसिएशन (ए.एम.एफ.आई.), बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (इरडा), पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.), कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) और अन्य ऐसी एजेंसियां भी कानून में कॉरपोरेट कॅरिअर प्रदान करती हैं.

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम : सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में एक कानूनी अनुभाग होता है जिसे कानून में योग्य कर्मियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है. उदाहरणों में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया आदि शामिल हैं. कुछ मामलों में ये उपक्रम अपनी चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा, सामूहिक चर्चा, सहित) साक्षात्कार आदि करते हैं. कंपनियों का एक और सेट अपने क्लैट स्कोर के आधार पर उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करता है. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक ऐसी ही कंपनी है.

मीडिया समूह : मीडिया समूहों में अवसर दो प्रकार के होते हैं. समाचार पत्रों और चैनलों में कानूनी रिपोर्टर / संवाददाता आदि होते हैं. मीडिया घरानों के प्रशासनिक सेट में कानूनी कर्मियों के पद होते हैं.

निजी क्षेत्र : हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, गोदरेज इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, प्रॉक्टर गैंबल जैसे बड़े कॉर्पोरेट्स की अपनी कानूनी टीम है. बड़ी अचल संपत्ति वाली कंपनियां, खाद्य और पेय पदार्थ कंपनियां आदि कानूनी कर्मियों को नियुक्त करती हैं.

परामर्श फर्म : इन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है. पहली श्रेणी में कानूनी परामर्श सहित विभिन्न क्षेत्रों में परामर्श सेवाएं आती हैं. फर्मों की अन्य श्रेणी विशेष रूप से कानूनी मामलों में काम करती है. ये फर्म नए और अनुभवी कानूनी पेशेवरों को नियुक्त करती हैं, जो फर्मों के ग्राहकों द्वारा निर्दिष्ट मामलों पर काम करते हैं. इस तरह की प्रतिष्ठित फर्मों के साथ इंटर्नशिप भी काफी महत्व रखती है.

कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग : ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के समान, कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग का भी एक बढ़ता हुआ बाजार है. कुछ कंपनियां कानूनी मुद्दों से संबंधित अनुपालन, अनुसंधान आदि के लिए बाहरी विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उठाती हैं. ऐसी फर्में हैं जो कानूनी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग की पेशकश करने के लिए ऐसे विशेषज्ञों को नियुक्त करती हैं.

सहायक कौशल

कानून में एक कॉरपोरेट कॅरिअर के लिए आपको मौखिक और लिखित संचार में बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें सामान्य और कानूनी मसौदा शामिल है. इसके अलावा, आपको सामाजिक रूप से जागरूक, जिम्मेदार और भरोसेमंद होना चाहिए, आपको अनुसंधान के लिए योग्यता के साथ एक विश्लेषणात्मक विचारक भी होना चाहिए क्योंकि कई मामलों में आपको अदालत के पिछले मामलों और निर्णयों के लिए गहराई से अध्ययन करना होगा ताकि आप किसी विशेष मामले की तैयारी कर सकें. आपकी व्यावसायिकता और सत्यनिष्ठा आपके रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करने में आपकी मदद करेगी.

यह लेख कानून में केवल कॉर्पोरेट कॅरिअर की बात करता है. कानून के स्नातकों के लिए विभिन्न अन्य कॅरिअर और रोज़गार के अवसर हैं जिन्हें इच्छुक लोग तलाश सकते हैं.

(लेखक मुंबई स्थित कॅरिअर काउंसलर हैं. ई-मेल: v2j25@ yahoo.in)

व्यक्त विचार व्यक्तिगत हैं.

(चित्र सौजन्य से: गूगल)